



The heart of  
Incredible India

# मध्य प्रदेश PRADESH



## POLICY FOR ESTABLISHMENT OF WELLNESS CENTRE/ RESORT IN THE STATE

BASED ON NATUROPATHY/ AYURVEDIC / YOGA/ TRADITIONAL THERAPY

# 2020





# Madhya Pradesh Emerging Potential Destination for Investment in Tourism Sector

## INVESTMENT OPPORTUNITIES

Convention Centre, Heritage Hotels, Hotels & Resorts, Golf Course, Camping / Adventure Sports, Water Sports, Film Studio , Rope Way

### Readily available Properties for Development

- 74 (1080 Hect.) Land Parcels at wildlife area, water bodies, leisure and Religious destinations.

- 13 (84 Hect.) Heritage Properties at famous Tourism destinations.

- 11 (278 hect) land parcels reserved for Ultra Mega Projects.



### Advantage Madhya Pradesh

24  
SANCTUARIES

11  
NATIONAL PARKS

06  
PROJECT TIGER RESERVES

03  
WORLD HERITAGE SITES

02  
RELIGIOUS SHIVA JYOTIRLINGAS

22  
NOTIFIED WATER BODIES

- Capital subsidy @15 % to 40 % on investment max. upto INR 100 Million.
- Special capital subsidy to Large, Mega and Ultra Mega Projects @ 30 %, Max. up to INR 9000 million in 4 Years.
- Special Incentive Scheme to setup Branded Hotel / Resort / Heritage Project.
- Attractive Film Tourism Policy – Incentive for film Making.
- Investor friendly Water Tourism, Camping & Adventure Policy.
- Support and Incentives to Setup Way Side Amenities.
- Online bid process for allotment of Govt Land and Heritage Buildings at suitable locations to Investors for 90 years on lease.
- The minimum reserved price is only Rs. 0.5 million per hectare in rural areas and Rs. 1 million per hectare in urban areas for land and Only 0.1 million for per heritage property.
- 1% lease rent per year of the premium amount.
- Land/ Heritage Property can be mortgaged to avail loans.
- Direct allotment of Land to investors for Ultra mega project (investment INR 10,000 Million +) for 90 years lease.



प्रदेश में प्राकृतिक/आयुर्वेदिक/योग/  
पारंपरिक पद्धति आधारित उपचार हेतु



# वेलनेस सेंटर/ रिसॉर्ट स्थापित करने की नीति 2020



# अनुक्रमणिका

उद्देश्य	03
परिभाषा	03
निवेशक चयन	05
परियोजना स्थापना हेतु भूमि का आवंटन	06
वेलनेस सेंटर/रिसॉर्ट हेतु अनुदान सुविधाएं	07
पर्यटन विभाग की भूमिका	09
नीति में संशोधन, स्पष्टीकरण/ मार्गदर्शन/समस्या निराकरण	10
नीति की प्रभावशीलता एवं अवधि	10

# CONTENTS

Objective	12
Definition	12
Selection of Investor	15
Procedure for allotment of Government land	15
Incentive/subsidy for Wellness Centre/Resort	17
Role of Tourism Department	19
Amendment/Clarification/ Guidance/Dispute Resolution	20
Enforcement/ Duration of the Policy	20





## 1. उद्देश्य

नीति का उद्देश्य प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्राकृतिक/ आयुर्वेदिक/योग/ पारंपरिक पद्धति आधारित संपूर्ण उपचार सुविधाओं सहित वेलनेस सेंटर/रिसॉर्ट स्थापित करना है ताकि प्रदेश संपूर्ण उपचार का एक केन्द्र बने तथा मेडिकल टूरिज्म की वृद्धि से प्रदेश में रोजगार के नये अवसर उपलब्ध हों।

## 2. परिभाषा

वेलनेस सेंटर/रिसॉर्ट से आशय प्रदेश की पर्यटन नीति अंतर्गत शासन द्वारा जारी निम्नलिखित पर्यटन परियोजना से है :-

A Wellness resort aim to revive energy, provide a platform for personal introspection, promote positive health, treat lifestyle diseases by providing different services such as Ayurveda, Naturopathy, spa, yoga, meditation, skincare treatment etc. Example of eligible Spiritual/Wellness centers – Ananda Spa, Jindal farms etc.

- 1 Auditorium or well-covered open area with seating capacity of a minimum 100 people.





- 2** Medicinal facilities with at least 8 well-trained staff.
- 3** Well-trained Yoga, Naturopathy, Ayurveda teachers with relevant recognized certifications.
- 4** Minimum 10 rooms, of quality equivalent to star/deluxe or above categories of hotels with minimum following requirements:-
  - 4.1** The facade, architectural features, and general construction of the building shall have the distinctive qualities of a luxury hotel.
  - 4.2** All single and double rooms shall have a floor area of not less than twenty-three (23) square meters, inclusive of bathrooms.
  - 4.3** All rooms must have bathrooms which shall be equipped with fittings of the highest quality befitting a luxury hotel with 24-hour service of hot and cold running water.
  - 4.4** There shall be a well-appointed lounge with seating facilities, a left-luggage room, and safety deposit boxes or lockers in the rooms.



- 4.5** There shall be a coffee shop and at least one specialty dining room which are well-equipped, well-furnished and well-maintained, serving high-quality cuisine and providing entertainment.
- 4.6** The kitchen, pantry, and cold storage shall be professionally designed to ensure efficiency of operation and shall be well-equipped, well-maintained, clean and hygienic.
- 4.7** There shall be a well-designed and properly equipped swimming pool, at least one recreational, sports facility and live entertainment facility in the establishment.
- 4.8** Adequate parking facilities.

### 3. निवेशक चयन

- 3.1** निजी भूमि पर परिभाषा अनुसार निजी निवेश से वेलनेस सेंटर/रिसॉर्ट स्थापित करने वाले निवेशक इस नीति में वर्णित सुविधाओं के पात्र होंगे ।
- 3.2** पर्यटन विभाग के आधिपत्य की शासकीय भूमि/परिसंपत्ति पर वेलनेस सेंटर/रिसॉर्ट स्थापित करने के लिये निवेशक का चयन भूमि की ऑनलाइन निविदा के माध्यम से किया जाएगा ।
- 3.3** अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (ऐसी परियोजना जिसकी लागत रूपये 100.00 करोड़ से अधिक) हेतु नियत भूमि पर निवेशक का चयन "प्रथम आओ प्रथम पाओ" के आधार पर किया जाएगा ।



## 4. परियोजना स्थापना हेतु भूमि का आवंटन

- 4.1** पर्यटन विभाग के लैण्ड बैंक की भूमि पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 में नियत प्रक्रिया अनुसार ऑनलाइन निविदा के माध्यम से आवंटित की जाएगी। निविदा हेतु शहरी क्षेत्र में भूमि की अपसेट प्राईज रूपये 10 लाख प्रति हेक्टेयर एवं ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 5 लाख प्रति हेक्टेयर होगी।
- 4.2** अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट हेतु "प्रथम आओ प्रथम पाओ" के आधार पर भूमि का आवंटन पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 नियत प्रक्रिया अनुसार साधिकार समिति द्वारा उस स्थान के तत्समय प्रचलित कलेक्टर द्वारा निर्धारित गाइडलाइन रेट पर की जाएगी।
- 4.3** उपरोक्तानुसार आवंटित भूमि अधिकतम 90 वर्ष की लीज पर पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन नीति अंतर्गत निर्धारित शर्तों पर दी जाएगी।
- 4.4** यदि निवेशक द्वारा लैण्ड बैंक के अलावा अन्य उपयुक्त शासकीय भूमि चिन्हित की जाती है तो ऐसी भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर उपरोक्त बिन्दु 4.1 एवं 4.2 अनुसार निवेशक को आवंटित की जाएगी।
- 4.5** आयुष विभाग के आधिपत्य की भूमि का दीर्घावधि, लीज/लायसेंस पर आवंटन विभाग द्वारा निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया अनुसार किया जा सकेगा।





## 5. वेलनेस सेंटर/रिसॉर्ट हेतु अनुदान सुविधाएं

**5.1** पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 के अंतर्गत वेलनेस सेंटर/रिसॉर्ट स्थापना पर किये गये पूंजी निवेश पर निम्नानुसार पूंजीगत अनुदान की पात्रता होगी :-

अनुदान योजना	न्यूनतम परियोजना व्यय (रूपये लाख में)	स्थायी पूंजीगत व्यय पर अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की अधिकतम सीमा (रूपये लाख में)	अन्य शर्तें
नवीन रिसॉर्ट एवं वेलनेस सेंटर (आयुर्वेद योग, नेचरोपैथी चिकित्सा सुविधायुक्त रिसॉर्ट) की स्थापना हेतु पूंजीगत अनुदान	500 लाख	15 प्रतिशत	200 लाख	भारत/ राज्य शासन द्वारा मान्य परिभाषा एवं मापदंडों/ मानकों के अनुसार इकाई की स्थापना आवश्यक है।

यदि इकाई की स्थापना नगर निगम क्षेत्रों के प्लान एरिया के बाहर की जाती है तो अनुदान का प्रतिशत 15% के स्थान पर 20% होगा बशर्ते कि ऐसी इकाई से 10 कि.मी. की परिधि में इकाई श्रेणी की अन्य कोई इकाई स्थापित न हो ।





**5.2** वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट होने की स्थिति में पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 अंतर्गत निम्नानुसार पूंजीगत अनुदान/निवेश प्रोत्साहन सहायता की पात्रता होगी :-

परियोजना श्रेणी	परियोजना श्रेणी हेतु न्यूनतम निवेश	परियोजना श्रेणी हेतु न्यूनतम (प्रदेश के लोगों को) रोजगार	इकाई द्वारा किये स्थाई पूंजी निवेश पर निवेश प्रोत्साहन सहायता का प्रतिशत	निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि की अधिकतम सीमा	वर्षवार निवेश सहायता राशि भुगतान का प्रतिशत			
					प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष
वृहद	रु. 10 करोड़ अथवा उससे अधिक	50	30%	15 करोड़	10%	10%	5%	5%
मेगा	रु. 50 करोड़ अथवा उससे अधिक	100	30%	30 करोड़	10%	10%	5%	5%
अल्ट्रा मेगा	रु. 100 करोड़ अथवा उससे अधिक	200	30%	90 करोड़	10%	10%	5%	5%





- 5.3** यदि वेलनेस सेंटर/रिसॉर्ट की स्थापना किसी ब्राण्ड के द्वारा की जाती है तो ऐसी इकाई को पर्यटन विभाग की "ब्राण्डेड होटल प्रोत्साहन नीति 2019" के प्रावधानों के अनुसार पात्रता होने पर अतिरिक्त अनुदान दिया जा सकेगा ।
- 5.4** उपरोक्त 5.1 से 5.3 कंडिका में वर्णित सुविधाओं का लाभ पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन नीति अंतर्गत निर्धारित नियम प्रक्रियाओं के अनुसार दिया जाएगा ।



## 6. पर्यटन विभाग की भूमिका

पर्यटन विभाग द्वारा मुख्यतः निवेशक चयन, भूमि आवंटन, परियोजना स्थापना हेतु फेसिलिटेशन एवं नीति अंतर्गत प्रावधित अनुदान एवं छूट उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा ।





## 7. नीति में संशोधन, स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन/ समस्या निराकरण

नीति में संशोधन हेतु मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग अधिकृत होगा तथा नीति क्रियान्वयन हेतु स्पष्टीकरण/ मार्गदर्शन/समस्या निराकरण के लिये पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति अधिकृत होगी ।



## 8. नीति की प्रभावशीलता एवं अवधि

यह नीति जारी होने के दिनांक से पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 के क्रियाशील रहने की अवधि तक लागू रहेगी । नीति की प्रभावशीलता संपूर्ण मध्यप्रदेश में होगी ।





# **POLICY FOR ESTABLISHMENT OF WELLNESS CENTRE/RESORT IN THE STATE**

**BASED ON NATUROPATHY/ AYURVEDIC / YOGA/ TRADITIONAL THERAPY**

# **2020**

**(In English)**





## 1. OBJECTIVE

The objective of the Policy is to develop such International standard Wellness Centre/Resorts through private investment which shall be based on Naturopathy/ Ayurvedic/ Yoga/ Traditional Treatment Therapy to provide treatment in totality and to create job opportunity through medical tourism in the State.



## 2. DEFINITION

The intent of such Wellness Centre/Resorts means a tourism project as defined in the tourism policy issued by the Government is as under:-

A Wellness resort aim to revive energy, provide a platform for personal introspection, promote positive health, treat lifestyle diseases by providing different services such as Ayurveda, Naturopathy, spa, yoga, meditation, skincare treatment etc. Example of eligible Spiritual/Wellness centers – Ananda Spa, Jindal farms etc.





- 1** Auditorium or well-covered open area with seating capacity of a minimum 100 people.
- 2** Medicinal facilities with at least 8 well-trained staff.
- 3** Well-trained Yoga, Naturopathy, Ayurveda teachers with relevant recognized certifications.
- 4** Minimum 10 rooms, of quality equivalent to star/deluxe or above categories of hotels with minimum following requirements:-
  - 4.1** The facade, architectural features, and general construction of the building shall have the distinctive qualities of a luxury hotel.
  - 4.2** All single and double rooms shall have a floor area of not less than twenty - three (23)square meters, inclusive of bathrooms.





- 4.3** All rooms must have bathrooms which shall be equipped with fittings of the highest quality befitting a luxury hotel with 24-hour service of hot and cold running water.
- 4.4** There shall be a well-appointed lounge with seating facilities, a left-luggage room, and safety deposit boxes or lockers in the rooms.
- 4.5** There shall be a coffee shop and at least one specialty dining room that is well- equipped well-furnished and well-maintained, serving high-quality cuisine and providing entertainment.
- 4.6** The kitchen, pantry, and cold storage shall be professionally designed to ensure efficiency of operation and shall be well-equipped, well-maintained, clean and hygienic.
- 4.7** There shall be a well-designed and properly equipped swimming pool, at least one recreational, sports facility and live entertainment facility in the establishment.
- 4.8** Adequate parking facilities.







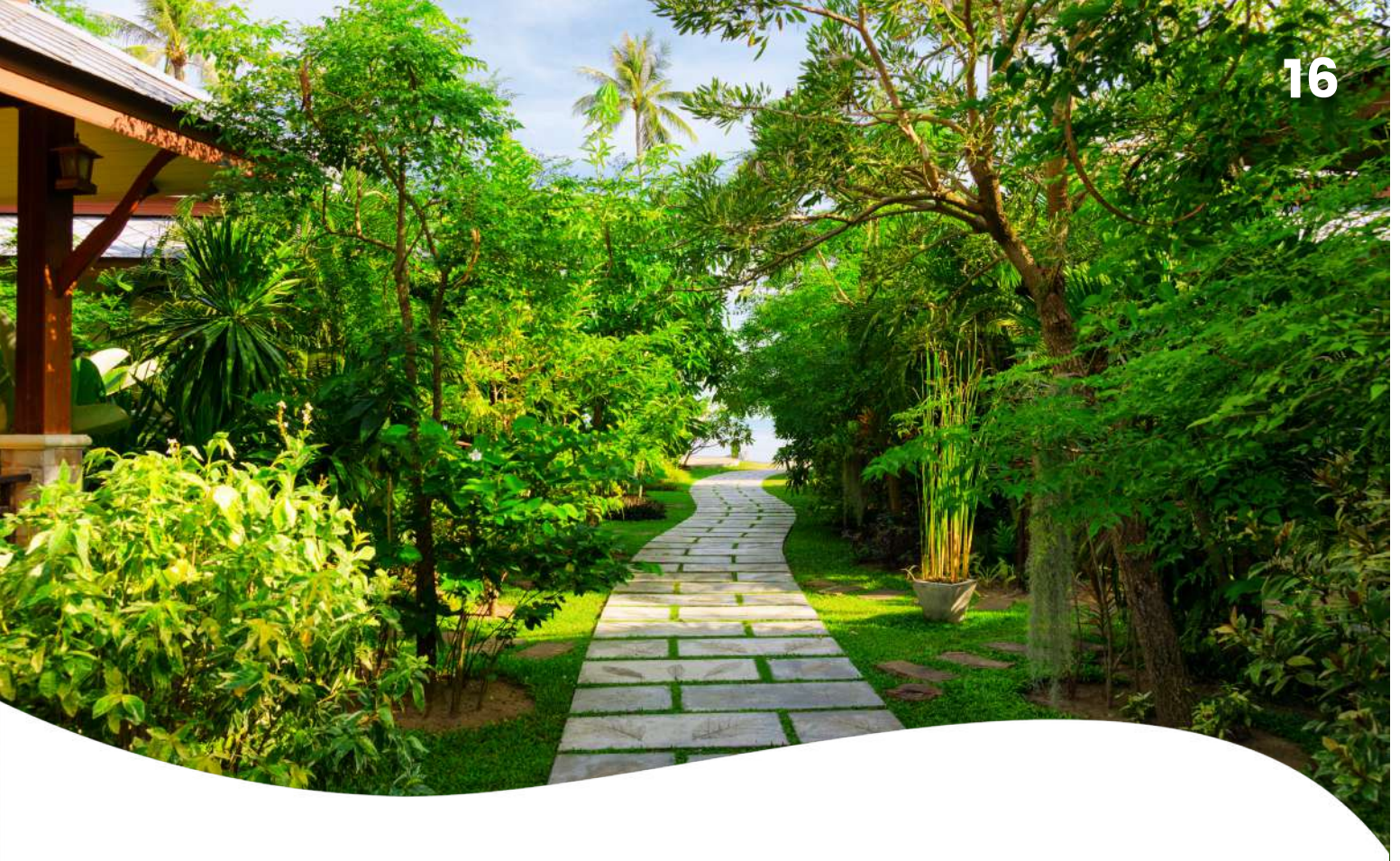
### 3. SELECTION OF INVESTOR

- 3.1 Any entity establishes such Wellness Centre/Resort on any private land shall be entitled to get all incentives mentioned in this Policy.
- 3.2 To establish a Wellness Centre/Resort on the Government land in possession of the Tourism Department shall be allotted to the investor through online bidding process.
- 3.3 Land parcels identified for Ultra Mega Project (A project having proposed investment not less than 100.00 crores) shall be allotted to the investor without bidding process on the basis of “First come First serve”.

### 4. PROCEDURE FOR ALLOTMENT OF GOVERNMENT LAND

- 4.1 Land parcels of the land bank of the Department of Tourism shall be allotted through online bidding process as described in the Tourism Policy (2016) amended 2019. The upset price of the land shall be Rs. 10.00 lakh per hectare in the urban areas and Rs. 5.00 lakh per hectare in rural areas.





- 4.2** For ultra-mega project land shall be allotted as per the procedure mentioned in the Tourism Policy (2016) amended in 2019 on “First come First serve” basis. The land cost shall be fixed by the Empowered Committee, constituted under the Tourism Policy, on the basis of current Collector’s guideline rates.
- 4.3** Land shall be allotted on 90 years lease as per terms & conditions prescribed in the Tourism Policy.
- 4.4** If the investor identifies any other Government land other than the land available in the Tourism Department’s land bank, firstly the said land shall be transferred to Tourism Department and thereafter shall be allotted to the investor according to clause No. 4.1 & 4.2 herein above.
- 4.5** Land in possession of Ayush Department shall be allotted on long term lease/license as per prescribed rules and procedure.



## 5. INCENTIVE/SUBSIDY FOR WELLNESS CENTRE/RESORT

**5.1** Following capital subsidy shall be given as per Tourism Policy (2016) amended 2019 for the establishment of Wellness Centre/Resort:-

Subsidy Scheme	Minimum Project Expenditure (Rs. in Lac)	Percentage of Subsidy against Fixed Capital Investment	Maximum ceiling of Subsidy (Rs. in lac)	Other conditions
Capital Investment subsidy for establishment of new Resort and Wellness Centre (Including Resort equipped with Ayurvedic, Yoga and Naturopathic treatment)	500	15%	200	Unit should be established as per the definition, criterion and standards defined by the Government of India/ State Government.

If the unit is being established out of planning area of the Nagar Nigam, the percentage of subsidy shall be 20% instead of 15% provided that there is no other unit of the same nature is existing within the 10 kms perimeter.

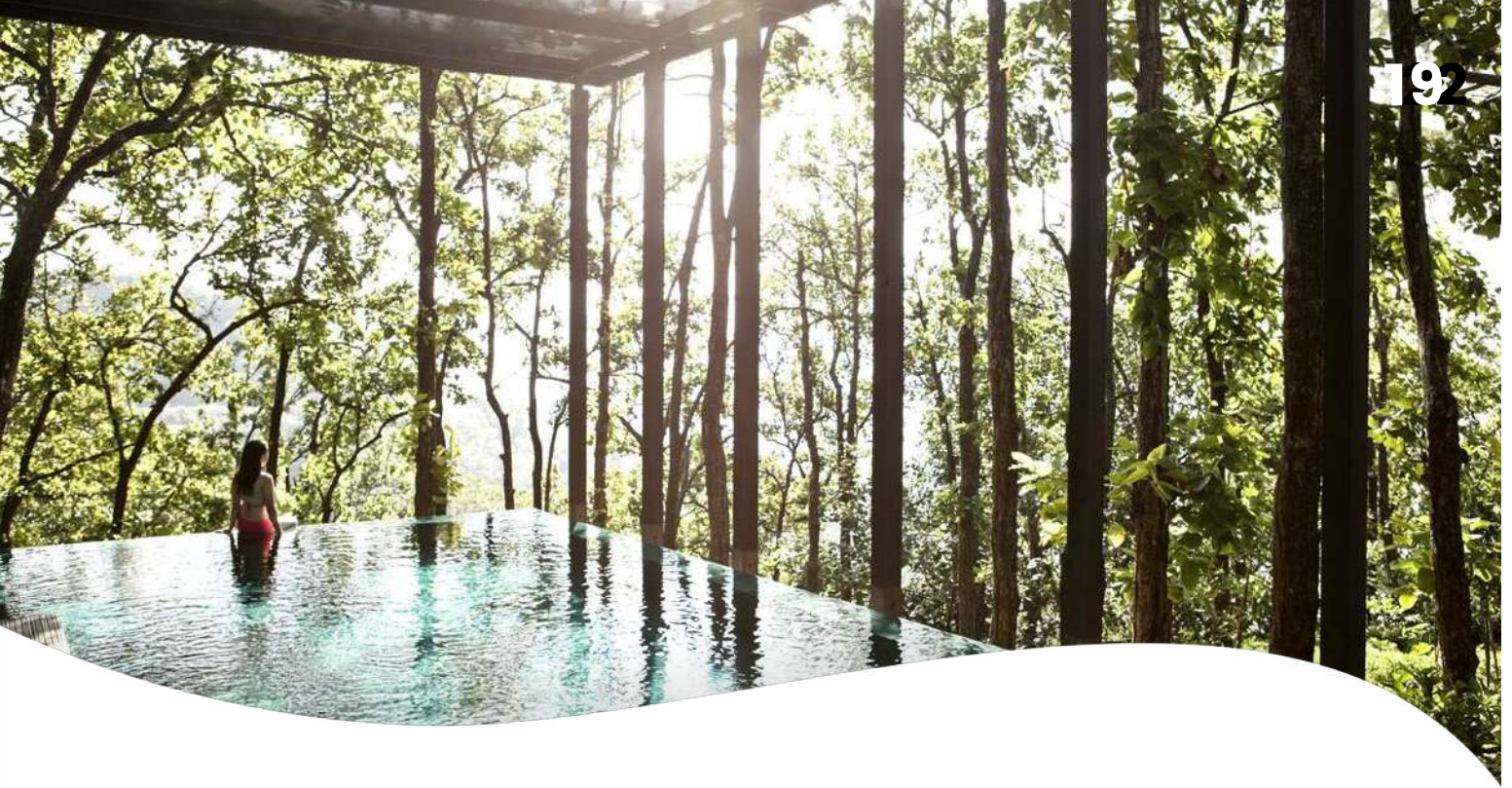




**5.1** For Ultra Mega Project the Capital Subsidy/Investment promotion as per the Tourism Policy (2016) amended 2019 shall be as under :-

Category of the project	Minimum investment in the project	Minimum number of employment (for residents of M.P.)	Percentage of Investment Promotion Assistance on capital investment made by the unit	Maximum ceiling of Investment Promotion Assistance (Rs in crore)	Year wise Percentage of Disbursement of Investment Promotion Assistance Amount			
					First year	Second year	Third year	Fourth year
<b>Large</b>	Rs. 10.00 crore or more	50	30%	15	10%	10%	5%	5%
<b>Mega</b>	Rs.50.00 crore or more	100	30%	30	10%	10%	5%	5%
<b>Ultra-mega</b>	Rs.100 crore or more	200	30%	90	10%	10%	5%	5%





- 5.2** If any brand establishes such Wellness Centre/Resort in such case it shall be given additional subsidy as per provisions of “Branded Hotels Promotion Policy, 2019” of the Tourism Department.
- 5.3** The benefits mentioned in clause 5.1 to 5.3 herein above shall be given as per rules and procedure laid down in the Tourism Policy.



## 6. ROLE OF TOURISM DEPARTMENT

Tourism Department shall mainly play a role in selection of investors, land allotment to facilitate investor in establishment of project and provide subsidy & exemptions etc. as per provisions of the Policy.





## 7. AMENDMENT, CLARIFICATION/GUIDANCE/ DISPUTE RESOLUTION

Department of Tourism, Government of Madhya Pradesh shall be authorized to amend the Policy and for implementation of the Policy the Empowered Committee constituted in the Tourism Policy (2016) amended 2019, under the Chairmanship of Chief Secretary, shall be authorized for clarifications /guidance /dispute resolution etc.



## 8. ENFORCEMENT/ DURATION OF THE POLICY

This policy shall be enforced from the date of issuance till the effectiveness of the Tourism Policy (2016) amended 2019. Policy shall be effective in whole Madhya Pradesh.

**NOTE:** For any clarification/interpretation notified Hindi version of this policy shall be referred.



# मध्यप्रदेश

पत्थरों पर उत्कीर्ण ऐतिहासिक पल और शौर्य की गाथाएं  
प्रेम, उत्साह, आतिथ्य और दैवत्व भाव से परिपूर्ण  
कुशल हस्तशिल्पियों की छेनी से उकेरी गई संवेदनशीलता की  
पराकाष्ठा  
बलखाती नदियां, हरियाली से आच्छादित पहाड़ियां और घाटियां  
शेर की दहाड़  
यह सम्मोहकता है बहुरंगी स्थलों के संगम की।



# मध्य प्रदेश PRADESH



The heart of  
Incredible India

## MADHYA PRADESH TOURISM BOARD



6th Floor, Lily Trade Wing, Above  
D-Mart, Jehangirbad, Bhopal - 462008,



0755-2780600/651/652



dirtpu.mptb@mp.gov.in, suresh.jhariya@mp.gov.in



[www.tourism.mp.gov.in](http://www.tourism.mp.gov.in)



@MPTourism



@mptourism



@MPTourism



@MPTourism

Designed By Onit Digital Creative Studio



World Heritage



Worship



Water



Wildlife



Wonders of Nature

# USP 5W

All combine to make  
**MADHYA PRADESH**  
a fascinating destination.